

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,

पंचायतीराज,

उ०प्र०।

2- समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ,

दिनांक- 10 दिसम्बर, 2018

विषय:- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का हस्तांतरण एवं उपभोग पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के हस्तान्तरण एवं ग्राम पंचायतों का व्यय पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाना है। उक्त के क्रियान्वयन हेतु समस्त सम्बन्धित इम्पलीमेंटिंग एजेन्सीज ग्राम पंचायतों को पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-बी०- 1-1206/दस-2017-एम०-39/2016 दिनांक 10.08.2017 द्वारा केन्द्रीय योजनाओं में इम्पलीमेंटिंग एजेन्सीज का पंजीकरण का कार्य पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर पूर्ण कर योजनाओं का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2- श्री संजीव पटजोशी, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-एम०-11015/307/2017-एफ०डी० दिनांक 20.03.2018 द्वारा प्रदेश में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से भुगतान कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के क्रम में दिनांक 09.10.2018 तक 58,807 ग्राम पंचायत संस्थाओं के सापेक्ष 55,897 का पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं 32,113 ग्राम पंचायत संस्थाओं का एप्रुवल किया गया है। दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

04.10.2018 की राज्य स्तरीय बैठक में श्री बाला प्रसाद, अपर सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्काल पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू कराने की अपेक्षा की गई है।

3- भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय से प्राप्त मार्ग निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित कार्यवाही दिनांक 15.12.2018 तक पूर्ण करा लिया जाये :-

- राज्य स्तर, जनपद स्तर व समस्त ग्राम पंचायतों का पी0एफ0एम0एस0 पर रजिस्ट्रेशन एवं एप्रुवल करा लिया जाये।
- ग्राम पंचायतों (प्रधान व सचिव) का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान के लिए मेकर एवं चेकर कार्य हेतु डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) तैयार करा लिया जाए।
- प्रिया साफ्ट पर समस्त ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2017-18 की समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कराते हुए वार्षिक पुस्तिका बन्द करा ली जाए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अद्यतन मासिक पुस्तिका तथा दैनिक पुस्तिका बन्द करा लिया जाए।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त ग्राम पंचायतों की कार्य योजना प्लान प्लस पर अपलोड कराई जाए।
- दिनांक 15.12.2018 तक समस्त डी.पी.एम. तथा ए.डी.पी.एम. को निदेशालय स्तर पर तथा समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को जनपद स्तर पर तथा सभी ग्राम प्रधानों को विकास खण्ड स्तर पर पी0एफ0एम0एस0 के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 द्वारा जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु रोस्टर तैयार कर तिथियां निर्धारित कर प्रशिक्षण करा लिए जाए।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ग्राम पंचायतों की धनराशि हस्तांतरण एवं भुगतान किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
- 8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 9- गार्ड फाइल।

आजा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।